वीणा शिवपुरी

बढ़ती आबादी आज एक जलता हुआ सवाल है। अपने-अपने तरीके से हरएक इस बारे में सोच रहा है और चिंतित भी है। चाहे वे देशी सरकारें हो या विदेशी ताकतें या आम लोग। खासतौर पर गरीब देशों की ग़रीब औरतें जो हर तरफ से दबाई जा रहीं हैं।

औरत पर परिवार का दबाव है ज्यादा बच्चे पैदा करने का, खासतौर पर बेटा जनने का। सरकार जोर देती है बच्चे रोकने पर। विकसित देश खूब अनुदान दे रहे हैं, जोर डाल रहे हैं कि विकासशील देशों में बढ़ रही आबादी पर रोक लगाई जाए।

औरत खुद क्या चाहती है? उसका अपना शरीर, उसका मन, उसकी परिस्थितियां क्या चाहती हैं? किसमें उसका भला है? इस सबकी किसी को चिंता नहीं है। इसलिए अब औरत को खुद अपनी चिंता करनी है। दूसरों के भरोसे रह कर खूब देख लिया। आज औरतें और उनके साथ काम करने वाले लोग आबादी के सवाल को औरतों के नज़रिए से परख रहे हैं, सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। अब समय आ गया है कि औरतें अपनी सोच को आवाज़ दें और समाज व सरकारों को सुनने पर मजबूर करें।

एक अच्छा मौका

इस साल कैरो (मिस्र देश) में विश्व की

सरकारें मिल कर आबादी के सवाल पर सोचेंगी और नीतियां तय करेंगी। ऐसी नीतियां जो आने वाले समय में दूर दराज के देशों, गांवों के लोगों के जीवन पर असर डालेंगी। खासतौर पर लाखों करोड़ों औरतों के शरीर और मन पर असर डालेंगी। उन पर नए-नए गर्भ निरोधक आजमाए जाएंगे। हर तरफ़ से दबाव बढ़ेंगे। उनके हक़ छिनेंगे।

'आबादी और विकास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' एक ऐसा मौका है जब सारी दुनिया की औरतों को आबादी के मसले पर अपनी राय पेश करनी चाहिए। ग़रीब देशों के ग़रीब लोगों को आबादी और विकास के नाटक का भंडाफोड़ करना चाहिए।

विकसित और धनी देशों ने अपने पैसे, सैन्य शक्ति और वैज्ञानिक तकनीक के बल पर ग़रीब देशों की सरकारों को खरीद लिया है। अब ग़रीबों की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं सिवाए खुद उनके। अब औरतों के प्रजनन हक़ों की बात करने वाला कोई नहीं सिवाए खुद उनके।

आबादी और विकास

आज तक यह बताया गया है कि दुनिया के संसाधन सीमित हैं और चूंकि आबादी बढ़ती जा रही है ये संसाधन कम पड़ रहे हैं और ग़रीबी बढ़ रही है। ज्यादा ग़रीबी और ज्यादा आबादी दोनों ही दुनिया के दक्षिणी देशों में है। ज़ाहिर है आबादी कम करने का दबाव वहीं ज्यादा है। यह पूरा तर्क काफी समझदारी का लगता है। कमी सिर्फ यह है कि कोई यह नहीं पूछता कि आज जितने संसाधन है क्या वे सारी आबादी में बराबरी से बांटे गए हैं? नहीं।

विकसित उत्तरी देश अपनी आबादी और अपने देश के संसाधनों की तुलना में कहीं ज्यादा संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है दक्षिणी देशों की ग़रीबी का। इसके लिए एक छोटा-सा उदाहरण काफी है। अमरीका में एक़ औसत व्यक्ति एक दिन में जितना पानी अपने गुसलखाने में बहा देता है उतना पानी कुछ अफ्रीकी देशों में एक पूरे परिवार को साल भर में पीने, खाने, नहाने के लिए नहीं मिलता। यही फ़र्क खाना, कपड़ा, मकान, इलाज, शिक्षा, हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। इस असमान बंटवारे की वजह से एक तरफ बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोगों और कुछ देशों के पास अपनी ज़रूरत से बहुत ज्यादा है। अगर दुनिया में ग़रीबी है तो उसकी वजह लोगों की संख्या उतनी नहीं, जितनी संसाधनों का असमान बंटवारा है।

इस मुद्दे पर सबका ध्यान खींचने की ज़रूरत है। इस अन्याय को मिटाने की ज़रूरत है। जो लोग अपने हिस्से से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वे तो इस मामले को उठाएंगे नहीं। इसलिए इसकी जिम्मेदारी पड़ती है उन पर जो इस अन्याय को भुगत रहे हैं। यानि अविकसित और विकासशील देश और उन देशों के भी निम्न वर्ग के लोग, खासतौर पर औरतें।

ग़रीबी और आबादी का चक्र

इन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है कि ग़रीबी और आबादी एक दूसरे के पीछे भागती हैं। अब तक के आबादी रोकने के अनुभवों ने एक बात साबित कर दी है कि ग़रीबों को अधिक बच्चों की ज़रूरत है। यही कारण है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल रहे हैं। वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और सरकार आम लोगों को चाहे मूर्ख समझते हों पर

सच्चाई यह है कि वे जानते हैं कि उनका अपना भला किसमें है।

— ग़रीबों के बच्चे होश संभालते ही मां-बाप की मदद करने लगते हैं। ये बच्चे परिवार पर बोझ नहीं हैं। उनकी अपनी बोली में अगर बच्चा एक पेट लेकर जनमता है तो दो हाथ भी लाता है।

— इनके बच्चों में बालमृत्यु दर बहुत अधिक है। ये अपने बच्चों को न पोषण दे पाते हैं, न उनके पास इलाज और देखभाल है। ज़ाहिर है अगर आठ-दस पैदा करेंगे तो ही दो-तीन बच्चे जवानी तक पहुंच पाएंगे।

— ग़रीबों के पास न बैंक खाता है, न जमीन जायदाद और न बंधी तनख्वाह या पैंशन। उनकी बीमारी, बेरोजगारी और बुढ़ापे में ये बच्चे ही काम आएंगे।

अगर ग़रीबी और आबादी का चक्र तोड़ना है तो ग़रीबों को हटाने की जगह ग़रीबी हटानी पड़ेगी। ज्यों ही निम्न वर्ग ऊपर उठता है और उसके पास बुनियादी सुविधाएं आती हैं, आबादी भी घटने लगती है।

औरत का दर्जा

आबादी कम करने की दिशा में औरत का बेहतर दर्जा भी कारगर साबित होता है। जब तक 50 फी सदी लोगों की यानि औरतों की कोई इज्जत नहीं होती, बेटे की चाहत कम नहीं होगी। औरतों का अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है। उन्हें बच्चों की संख्या का फैसला लेने का हक़ नहीं है। अपनी मर्जी का गर्भ निरोधक पाने की सुविधा नहीं है। ये सभी मुद्दे न सिर्फ औरत का सामाजिक दर्जा दर्शाते हैं बल्कि आबादी पर भी असर डालते हैं।

चारों ओर से बढ़ती आबादी के खिलाफ़ शोर सुनाई देता है, लेकिन इस समस्या के सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर कोई संतुलित सोच सामने नहीं आती। इस पूरी खींचतान में औरत का शरीर, उसका स्वास्थ्य, उसकी इच्छाएं कुर्बान हो रही हैं।

हमें इस पर एतराज़ है। हमें चाहिए ऐसी जनसंख्या नीतियां जो औरत के बुनियादी हक़ों की रक्षा करते हुए उसके तन-मन और भावनाओं की इज्जत करें। □